शिक्षित बनो ! संगठित रहो !! संघर्ष करो !!!

Rashtriya Shoshit Parishad (Regd.) No.: S/13390

(Recognised by the Govt. of India & exempted U/S 80G of the Income Tax Act. 1961)

राष्ट्रीय शोषित परिषद् (रजि०)

(A Council for the Welfare of SC/ST)

President :
JAI BHAGWAN JATAV
Tel. : 26192066
Mob. : 9810634677, W : 9810634655

B-2 Extn./2,
St. No. 7, Krishna Nagar,
Safdarjung Enclave,
New Delhi-110029

Ref. ..... No. RSP/2018/PMO/ 5897

Dated ..... 25th August, 2018

सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार, 152 साऊथ ब्लॉक
नई दिल्ली – 110011

विषयःसरकारी पूंजी/धनराशि से बैंकों को दी जाने वाली सहायता (Grant in Aid) के विरोध में पत्र

ज्ञापन

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। आपका मुख्य कार्य देश में बढ़ रहीं बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण इत्यादि से देश की जनता को निजात दिलाना भी था। परन्तु आपने देश में बढ़ती भुखमरी, कुपोषण, स्वास्थय, शिक्षा इत्यादि पर कोई ध्यान न देते हुए अमीरों को ही माला–माल करने का बीड़ा उठाया हुआ है, जो कि देश की जनता को कतई पसंद नहीं है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 2300 से भी अधिक करोड़पति लुटेरे देश को लूट कर एवं देश छोड़कर भाग भी चुके हैं। आप यह भूल गये कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहे वह बीड़ी पीने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो वह भी सरकार के खज़ाने में टैक्स के रूप में भले ही 2 पैंसे ही देता हो उसको भी बराबर का हक है। देश में आय का श्रोत केवल मुख्य रूप से जनता ही है और जनता के द्वारा दिया गया टैक्स चाहे वह किसी भी रूप में ही क्यों न लिया गया हो, उसी पैसे से देश की सरकार चलती है। जनता से जो कर (Taxes) लिये जाते हैं, उस पैसे का सदुपयोग करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। जनता से कर (Taxes) के रूप में इक्ट्ठे किये धन को लुटाने की इजाजत आपको नहीं दी गयी है। आप केवल इस धन के संरक्षक (Custodian) ही हैं। लेकिन आपको जनता से वसूले गये धन को लुटाने का कोई अधिकार नहीं है। आम नागरिक से वसूला गया अधिकतर धन नौकरशाहों, राजनैतिक नेताओं की जेब में भ्रष्ट्राचार के रूप में पहुंच जाता है। आज भारत लगभग 80 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और इसके बावजूद भी विश्व बैंक से कर्ज उठाने की होड़ लगी हुई है। घी पीयो उधार लेकर, सेहत बनाओ कर्ज लेकर, यह कहावत भारत सरकार पर चरितार्थ हो रही है। सरकार के पास धन की कमी होने का रोना रोया जाता है और कोई भी नई योजना देशवासियो के लिए नहीं लायी जा रही हैं जिससे कि देश की भुखमरी मिटे, रोजगार पैदा हों, गरीब को स्वास्थय लाभ मिले। प्रत्येक नागरिक के बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले और भुखमरी पर कुछ न कुछ राहत मिल सके। सरकारी एवं गैरसरकारी स्तर पर अनेकों रिपोर्टें आ चुकी हैं, जिसमें देश की आंतरिक स्थिति का वर्णन किया गया होता है। उल्लेखनीय है कि महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गयी है। मुख्य रूप से आपके शासनकाल में दवाईयों की कीमत बेहताशा बढ़ा दी गयी है। चारों तरफ त्राहि–त्राहि मची है। यही नहीं बल्कि देश में गदर का माहौल बना हुआ है।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की आर्थिक स्थिति किसी भी रूप में सुदृढ़ नहीं है बल्कि कमज़ोर स्थिति में है और जो भी योजनाएं और कार्यक्रय बनाये जाते हैं वे लगभग सभी कार्यक्रम देश के अपने

पैसे से नहीं बल्कि उधार या कर्ज उठाकर ही बनाये जाते रहे हैं। इसी के चलते देश लगभग 80 लाख करोड़ रूपये कर्ज में डुब चुका है जिसकी वजह से कुल बजट की लगभग 24 प्रतिशत धनराशि ब्याज के रूप में ही देनी पड़ रही है। यदि 80 लाख करोड़ रूपये का कर्ज न उठाया गया होता तो जो धनराशि ब्याज के रूप में प्रतिवर्ष देनी पड़ रही है यदि यह 6–7 लाख करोड़ रूपये की धनराशि को बचा कर देश के विकास कार्यों में खर्च की जाती, तो कुछ वर्षों में ही देश की भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि जैंसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो सकती थी। कोई भी आम नागरिक कर्ज (Loan) लेने से पहले उसके ब्याज चुकता करने पर अपना दिमाग लगाता है और वह अगला कर्ज तभी उठाता है या लेता है जबकि वह पहले कर्ज को चुकाने की उसकी क्षमता हो।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप की सरकार 80 लाख करोड़ के कर्ज में पहले से ही डूबी हुई हैं और भारत सरकार की क्षमता ही नहीं है कि वह बुलेट ट्रेन जैसे कार्यक्रम अपने फण्ड से चला सकें। जबकि हम जिद (Stubborn) पर अड़े हैं कि बुलेट ट्रेन जरूर आयेगी। यह बड़े ही दुखः और शर्म की बात है कि भारत सरकार हमेशा कर्ज़ा उठाकरके ही कोई नई योजना लाती है। लेकिन किसी भी सरकार ने अपने समय में उस कर्ज को चुकता करने की तनिक (least efforts) भी कोशिश नहीं की और कर्ज़ा दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

आदरणीय, प्रधानमंत्री जी, गत वर्ष में आम जनता से करों (Taxes) के रूप में इक्ट्ठा किया गया धन जो कि देश के विकास में ही लगना था वह धन भी बरबाद किया गया है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि गत वित्त वर्ष 2017–18 में 90 हजार करोड़ रूपया बैंकों को सहायता (Grant in Aid) के रूप में दिया गया और चालू वित्त वर्ष 2018–19 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 65 हजार करोड़ रूपये की सहायता (Grant in Aid) की योजना बनायी गयी है। यह धन आम जनता से टैक्स (Tax) के रूप में वसूला गया धन है। इस धनराशि को भारत सरकार किसी भी एजेंसी को खैरात (Doles) के रूप में नहीं दे सकती। क्योंकि ये किसी के बाप का दिया हुआ व्यक्तिगत (Individual) धन नहीं है। हमारी संस्था भारत सरकार के इस प्रकार से धन को बैंकों को सहायता राशि (Grant in Aid) के रूप मे देने का पुरजोर विरोध करती है। यदि भारत सरकार आम जनता के द्वारा अदा किये गये कर (Taxes) इत्यादि के रूप में वसूली गयी धनराशि को बैंको को देने से नहीं रोका गया तो देश की सबसे बडी अदालत **"जनता की अदालत"** में इस मामले को उठाया जायेगा। इसीलिए मैं, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बैंको के साथ ज्यादा हमदर्दी न करके जो गरीब जनता भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, निरक्षरता का शिकार है एवं शिक्षा से वंचित है, सबसे पहले इन ज्वलन्त समस्याओं को सुलझाएं। आपके 4 वर्ष के प्रधानमंत्रीत्व काल में महंगाई कई गुणा बढ़ी है, यहाँ तक कि दवाइयों के दाम तो सबसे अधिक तक बढ़े हैं और दवाईयों की कीमतें तो आसमान छू रहे हैं। देश का गरीब तबका अपने बच्चों को दवाई दिलाने में भी असमर्थ है बिना दवाई के बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कृपया इसके ऊपर अपना ध्यान अवश्य ही केन्द्रीत करें।

यदि बैंकरस अपनी गलत कारगुजारी के कारण आर्थिक स्थिति/तंगी से जूझ भी रहे हैं तो वह बोण्ड द्वारा या अपने शेयर बेच कर या कर्ज लेकर, या किसी अन्य रूप में धन इक्ट्ठा करके अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। मैं, आपसे यह भी आग्रह करना चाहुंगा कि गत वर्ष दिया गया 90 हजार करोड़ रूपया भी बैंको से ब्याज सहित वापिस लिया जाये। जो योजना आपने बैंकों को 65000 करोड़ रूपये और अधिक देने या लूटाने की जो योजना बनायी है उस पर तुरन्त रोक लगायी जाये तथा यह धनराशि, देश में व्याप्त कुपोषण को दूर करने, गरीबी मिटाने, बेरोजगारी दूर करने, भुखमरी मिटाने पर ही खर्च की जाये। याद रहे आपकी अच्छी या बुरी कारगुजारियों को इतिहास मे अंकित अवश्च किया जायेगा।

धन्यवाद सहित,

भवदीय

Bhagwan

(जय भगवान जाटव)

अध्यक्ष